इन्वेस्ट यूपी के फ्रांस डेस्क ने इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने लिए किया संवाद

उत्तर प्रदेश-फ्रांस व्यापार सहयोग को नई गति, इन्वेस्ट यूपी और आईएफसीसीआई की रणनीतिक बैठक से निवेश को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, 17 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश में फ्रांसीसी निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, **इन्वेस्ट यूपी के फ्रांस डेस्क** ने **इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईएफसीसीआई)** के साथ एक उच्चस्तरीय ऑनलाइन बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता इन्वेस्ट यूपी के **अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शशांक चौधरी** ने की।

आईएफसीसीआई (IFCCI) के बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रमुख **श्री गिलॉम विगियर और वरिष्ठ सलाहकार श्री आशीष शुक्ला** ने आगामी निवेश रोडशो और B2B कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री विगियर ने बताया कि फ्रांस की स्वतंत्र व्यापार संस्था 'बिजनेस फ्रांस' से जुड़ी लगभग 850 कंपनियों को उत्तर प्रदेश के निवेश अवसरों से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं।

श्री चौधरी ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक मजबूती को रेखांकित करते हुए राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की उपलब्धता, 24 करोड़ से अधिक के उपभोक्ता आधार और निवेश अनुकूल नीतिगत ढांचे को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने यूपी फॉर्च्यून ग्लोबल, इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जैसी प्रमुख योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यूपी में वैश्विक स्तर की प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। एफडीआई नीति के तहत भूमि सब्सिडी, पूंजीगत व्यय सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जिसके कारण यूपी भारत का सबसे प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है।

बैठक में व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस), औद्योगिक विविधीकरण, आपूर्ति श्रृंखला ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, जीसीसी, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसमें भविष्य में होने वाले वर्चुअल निवेश संवाद, क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल भ्रमण आदि शामिल है।

इन्वेस्ट यूपी फ्रांसीसी निवेशकों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट निवेश नीतियां, जीआईएस आधारित भूमि बैंक विवरण और अनुकूलित नीति सारांश साझा करेगा, जिससे डेटा-आधारित निवेश संवाद को बढ़ावा मिलेगा।